[श्री भोगेन्द्र झा]

का प्रयास किया है कि यह हिन्दी की डायलेक्ट, उप-भाषा है या भाषा है, तो इस में जिन भाषाओं का जिक्र मैं ने किया है उस में हिन्दी की उपभाषा एक भी नहीं हो सकती है। हिन्दी से ऊपर की सीढ़ी में वह जा सकती हैं, उन की बहन हो सकती हैं, उस की दादी हो सकती है।

श्री हुकम चंद कछवाय : बेटी भी हो सकती हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं। बेटी नहीं हो सकतीं है। बेटी वह हो सकती है जिसका जिक्र आप ने किया है। लेकिन यह पुरानी भाषाएं हैं। इसलिए मैं ने कहा कि मैथिली का साहित्य 1 हजार साल का अभी मौजूद हैं। इस के पहले का नहीं है। काव्य के रूप में इस का साहित्य मौजूद है। डा० रानेन सेन जी ने जिक्र किया है विद्यापति के समान कवि इस में हुए। कई-कई सौ साल पहले का साहित्य मौजूद है और आज यह एक समृद्ध भाषा है जिस में लोग अपना काम करते हैं। जिस काम के लिए आप रोक देते हैं उस को छोड़ कर बाकी सभी उसी भाषा में वह लोग करते हैं। इसी तरह राजस्थानी में भी मीराबाई से लेकर आगे तक साहित्य है। और उस से पहले भी यह भाषा थी, इसीलिए तो मीराबाई के जरिये इतने जोरदार ढंग से उस का इजहार हुआ। और जैसा कि आप सुन चुके हैं, सन् 1905 ई० से अंग्रेजों के जमाने से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मैथिली को स्थान दिया गया था और आज तो कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस और बिहार के विश्वविद्यालयों में भी उस को स्थान मिला हुआ है। इस पृष्ठ भूमि में जो मंत्री महोदय ने कहा कि इस को लोग बढ़ावा दें तो लोग बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजों ने मातृभाषाओं को कुचला और दबाया और अंग्रेजी को ऊपर से लाद दिया। इसलिए हमारी विभिन्न मातृभाषाएं अंग्रेजी जमाने में दबाई गईं, कुचली गईं। और कुछ उस के पहले से भी कुचली गईं क्योंकि सरकारी भाषा लोगों पर लादी जाती रही, चाहे वह फारसी हो, अंग्रेजी हो या कुछ भी हो और बाकी मातृभाषाओं को दबाया जाता रहा। यह कुछ हजार वर्षों से हमारे यहां यह अड़चन चलती रही और अंग्रेजी राजमें अंग्रेजी जोरदार ढंग से लाद दी गई। लेकिन यह पुरानी भाषाएं आज भी लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। मैथिली में तो प्राथमिक से ले कर स्नातकोत्तर तक शिक्षा हो रही हैं। भोजपुरी के बारे में कहा कि जो उन को फिल्मों का हाल रहा, कितनी मिठास उन में थी, मैं ने साइकिल रोक कर उस का गाना सुना, मैं साइकिल पर चल रहा था, उस का गाना सुना तो साइकिल का पैडिल रोक कर मैं ने उस का गाना सुना। राजस्थानी का जिक्र भी आपने सुना। संविधान के आठवें शेड्यूल में 15 भाषाएं हैं उनमें से कइयों से यह भाषाएं ज्यादा समृद्ध भी हैं, और ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल भी होती हैं। उन से कइयों से ज्यादा पुरानी हैं। लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में और इस्तेमाल में लायी जाती हैं। कहते हैं कि आठवें शेड्यूल में रखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है जरूरत तो 15 को क्यों रखा हैं? मैं यह नहीं समझता कि मंत्री जी के कहने का यह मतलब है कि बिना सोचे समझे रख दिया।

सभापति महोदय : अब आप दूसरी बार बोलिएगा।

17.28 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION *RE* : EXPENDITURE ON GANDAK PROJECT

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति जी, आज मैं जो आधे घंटे की चर्चा उठाने जा रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैंने एक प्रश्न दिया था 29-6-71 को तारांकित प्र० संख्या 787, उसी के जवाब के बाद मुझको आवश्यकता पड़ी कि मैं आधे घंटे की चर्चा कराऊं। यह गंडक प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए

सन् 1952 से यहां आने के बाद से मैं प्रयत्न करता रहा हूं कि इसको सरकार स्वीकार करे और इसके लिए मैंने भागीरथ प्रयत्न किया। खुशी की बात है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की जिन्दगी में, उनकी मौजूदगी में उसका शिलान्यास हुआ और उसको बाल्मीकि नगर कहते हैं, उसके बाद से लेकर आज तक यह गंडक प्रोजेक्ट चालू है और चल रहा है। इस गण्डक प्रोजेक्ट का 1961 का पहला तखमीना था—52 करोड़ 3 लाख रुपये। उसके बाद 1965 में फिर तखमीना लगाया गया और फिर 1969 में यह तय पाया कि इस पर 158 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च होगा। अब 1971 आ गया है, अब इस पर कितना खर्च पड़ेगा, यह पता नहीं है। गण्डक के बारे में इधर इन लोगों ने हिसाब लगाया है कि 8 करोड़ रुपया ड्रेनेज पर खर्च होगा, क्योंकि जब पहले गण्डक का काम शुरू हुआ था, तब इन्होंने भांपा नहीं था, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर साढ़े छः करोड़ रुपया खर्च करना होगा और जो कीमत बढ़ गई है, लेबर और दूसरे सामान की, उसके कारण 10.12 करोड़ रुपये का अन्दाज लगाया है, जो कि अब खर्च होगा। कहने का मतलब यह है कि 24.62 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो कि मिला-जुला कर 25 करोड़ हो जायगा।

17.29 hrs.

[SHRIMATI SHEILA KAUL *in the Chair*]

इस गण्डक प्रोजेक्ट पर 1970-71 तक 80 करोड़ 60 लाख रुपया बिहार में खर्च हुआ है, जिसमें से 12 करोड़ 2 लाख रुपया नैपाल पर खर्च हुआ है, 33.59 करोड़ यू० पी० में खर्च हुआ है, जिसमें से 80 लाख रुपया नैपाल में खर्च हुआ है।

यह तिरहुत कैनाल सब से बड़ी कैनाल है जो 159 मील लम्बी है, आर० डी० 704 तक इसका निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अन्तर्गत सिंचाई की 5 लाख एकड़ जमीन आती है। अभी इसमें फील्ड चैनल्ज नहीं बनी हैं, पहले 2 क्यूजेक्स कैपसिटी तक की चैनल्ज बनाने का विचार था, लेकिन अब 1 क्यूजैक ही बनाई जा रही हैं। आगे चल कर इस में फील्ड चैनल्ज कब बनेंगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो खर्चा गण्डक का हो चुका है, उस खर्चे से क्या फायदा हुआ? 50 हजार एकड़ जमीन बिहार में ईस्टर्न कैनाल से और 70 हजार एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में अब तक पटी है, इन दोनों को मिलायें तो 105 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्च हो चुका है लेकिन अब इस से आमदनी क्या है—गण्डक से 1 लाख 26 हजार रुपया आप का निकला है—निकला है या निकलना है भगवान जाने। प्रश्न यह है कि गण्डक प्राजेक्ट का काम क्यों नहीं चल रहा है। एक जगह इन्होंने बतलाया है कि इस के पानी का यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है। चेयरमैन साहबा, मैं पूछना चाहता हूं मैं अपने जिले के बारे में ही बतलाना चाहता हूं, अंग्रेजी राज्य के जमाने से एक कैनाल थी। उस कैनाल से हम देखते थे कि जिसके हाथ में 10 एकड़ जमीन है, उसके दरवाजे पर हाथी झूमता था, लेकिन जिस के पास 100 एकड़ जमीन है, वह भूखा मर रहा है। हम लोग इरिगेशन माइंडेड हैं, लेकिन ये पानी नहीं देते हैं और कहते हैं कि यूटिलाइज नहीं करते हैं। गर्मी के वक्त पानी नहीं दिया, अगहनी के बीज के वक्त पानी नहीं दिया लेकिन जब वरुण देव पानी दे रहे हैं तो नहरों, में भी पानी छोड़ दिया हैं। नतीजा यह हुआ है कि एक तरफ वरुण देव का पानी और दूसरी तरफ इन की नहरों का पानी, दोनों मिल कर हम लोगों के घर डुबा रहे हैं। ये कहते हैं कि किसान पानी नहीं लेता है, समय पर पानी देंगे तभी तो वह पानी लेगा, लेकिन उस समय पानी नहीं देते हैं।

दूसरी बात—गण्डक में जो रुपया खर्च हुआ है—क्या सरकार ने कभी अन्दाजा लगाया कि कहां खर्च हुआ है, प्रोजेक्ट पर कितना खर्च हुआ, मिट्टी के काम पर कितना खर्च हुआ, पुल बनाने पर कितना खर्च हुआ—सरकार के पास इसकी

[श्री विभूति मिश्र]

कोई इवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है। मैंने राव साहब को लिखा था कि एक इवैल्यूएशन कमेटी बनाइये जो जांच करे कि जो इतना रुपया खर्च हुआ है, वह सही खर्च हुआ है या गलत खर्च हुआ है। अगर गलत खर्च हुआ है तो कौन आदमी हैं जो उसके लिये जवाब-देह हैं। नुनिया गांव का पुल बह गया, तीन लाख का पुल था।

बाल घाट के नीचे साइफन टूट गया, अब देखता हूं कि उस की मरम्मत हो रही है। तो यह सब जो खर्चा हुआ वह केन्द्रीय सरकार का पैसा है, केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट को देती है इसलिए केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना चाहिए कि यह जो पैसा हमारा लग रहा है वह सही लग रहा है या नहीं? उसका उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं और बीच में उसको कोई खा तो नहीं जाता है।

डा० राव से मेरी एक शिकायत है। जब ये वहां जाते हैं तो इंजीनियर्स डर जाते हैं। इसलिए दो साल से ये गए नहीं है। अगर ये जाते तो मैं समझता हूं कम गड़गड़ होती। मैं आग्रह करूंगा कि ये वहां पर जायें।

अलावा एक बात यह कहते हैं कि लोगों ने जमीन देने में कोताही की लेकिन मैं इस सदन में इस बात को जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करता हूं। इतनी बड़ी कैनाल निकाली गई है जोकि देखने में नदी साबूम होती है उसमें गांव के गांव और घर के घर ले लिए गए लेकिन किसी ने कोई एतराज नहीं किया। पहले बड़ी नहर निकली और फिर ब्रांच कैनाल्स निकली—इतना बड़ा काम हुआ लेकिन लोगों ने कहीं पर कोई एतराज नहीं किया। कुछ थोड़े से एतराज थे तो मैंने जाकर लोगों से पूछा और वह दूर कर दिए गए। लेकिन एतराज क्यों होते हैं वह मैं बताना चाहता हूं। इनके यहां पहले आज तक सर्वे नहीं हुआ और एलायनमेंट बिना ये मिट्टी काटने के लिए चले गए और फिर जहां जैसे चाहा, कहीं उल्टा और कहीं सीधा लाइन को लगाया। उसमें लोगों ने एतराज किया। कुछ लोगों ने विभागीय लोगों को खुश किया तो उन्होंने बजाये सीधा निकालने के उल्टा लाइन निकाल दिया। तो इसी बात पर असल में लोगों को एतराज होता है। इसके बावजूद भी मैं वहां गया और लोगों से कहा कि नहर निकालने दो और जो भी कठिनाई हो उसको सह लो। लोगों ने कहा ठीक है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि नहर निकालने में लोगों ने बाधा डाली है बल्कि प्रश्न यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने जो इंजीनियर रखे उन्हीं लोगों ने उसमें सारा गोलमाल किया और उससे जनता को बड़ी तकलीफ है। आप के जो चीफ इंजीनियर हैं वह तो पटना में रहते हैं और वहां से गंडक नहर सौ मील दूर है। चीफ इंजीनियर को पटना में रहने की क्या जरूरत है? राव साहब कहते हैं कि चीफ इंजीनियर का हेडक्वार्टर गंडक कमांडेट एरिया में रहे लेकिन इनकी बात को कोई मानता नहीं। चीफ इंजीनियर पटना में ही रहते हैं और एक हवाई जहाज है जिससे उड़कर भौसालोटन जाते हैं और इस तरह थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि चीफ इंजीनियर जब वहां नहीं रहते हैं जोकि उसको देखने वाले हैं तो फिर वहां की क्या हालत होगी?

ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि सरकार एक इवैलुएशन कमेटी बनाये और उसमें निष्पक्ष आदमी रखे—कनवार सेन जैसा इंजीनियर हो तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि इस पर अभी आधा खर्चा हुआ है और आधा खर्चा बाकी है इसलिए मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसको ले लें। जब फखरुद्दीन साहब इसके मिनिस्टर थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ले लेंगे लेकिन उस समय बिहार गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। उसके बाद आयंगर साहब ने भी लिखा कि इसको केन्द्रीय सरकार ले ले लेकिन उस समय जो वित्त मन्त्री थे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि दो स्कीमों को—एक तो ककड़ापाड़ा और दूसरी का नाम

मुझे याद नहीं—केन्द्रीय सरकार ने लिया और उनको बना कर फिर वापिस किया। इस लिए मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसको ले ले तो सर्वोत्तम होगा और बहुत जल्दी काम हो जायेगा। इसका नैपाल राज्य से, उत्तर प्रदेश से, और बिहार से सम्बन्ध है इस लिए यह उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार इसको ले ले।

माननीय राव साहब गंडक योजना का काम देखें और विजिट किया करें। गंडक कमान्ड एरिया के एम० पी० लोगों का एक बोर्ड बने जो वहां की स्थिति को देखा करे।

चीफ इन्जीनियर का हैडक्वार्टर गंडक कमान्ड एरिया में रहे। ड्रेनेज स्कीम जो बनाने जा रहे हैं उसका इंजीनियर इंचार्ज गंडक प्रोजेक्ट इंजीनियर्स में से न रहे, बल्कि इंडिपेंडेंट इन्जीनियर दिया जाय। उसका गंडक प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक न हो। गंडक प्रोजेक्ट को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले तो अच्छा रहे। और अगर केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में न ले तो इसके लिए बिहार सरकार को उचित पैसा दे ताकि काम ठीक से चल सके।

जो अधिकारी वहां हैं उनको तत्काल बदल दिया जाय। क्योंकि उनके रहने से गंडक प्रोजेक्ट में जो गड़-बड़ी हुई है वह आगे न हो सके, और जांच भी निष्पक्ष हो सके। पुराने इंजीनियर्स को वहां से हटा कर दूसरे इंजीनियर वहां रखें।

इसी तरह विलेज चैनल के बारे में सरकार ने कहा था लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ। अगर सरकार ऐलाइनमेंट कर दे तो गांव वाले विलेज चैनल के लिये तैयार हैं। गंडक प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च हो रहा है और यह खर्चा रैयत से वसूल होगा जो वह नहीं देगी क्योंकि उसको उस योजना से कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। पुराने जो ऐस्टीमेट हैं उससे खर्च बढ़ता ही जाता हैं। सरकार जल्दी से जल्दी इस योजना को पूरा करे। जो विलेज चैनल निकले उसके लिये सरकार पहले से बता दे। सर्वे और अलाइनमेंट के लिये आप पहले से लोगों को बता दें। जमीन के सम्बन्ध में कार्यवाही करें ताकि काम में विलम्ब न हो। और जिन लोगों का कमपेन्सेशन बाकी है और जमीन ले ली गयी है उन्हें कमपेन्सेशन जल्दी से जल्दी सरकार दे। और जो काम आगे बढ़ें उसको पूरा करते चलें। ऐसा न हो जैसे सारन जिले में हुआ है कि जहां-तहां जमीन खोद दी है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। जमीन खुदी हुई पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिये। जो काम हाथ में लें उसको पूरा कर के आगे बढ़ते जायें और इवर इरीगेशन पोटेन्शिएल को क्रीएट करते जायें ताकि लोगों को मालूम हो कि किस तरह योजना से हम को लाभ हो रहा है।

अन्त में इतना ही कह कर बैठता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस योजना को अपने हाथ में ले ले और हाथ में लेकर काम को बढ़ाये।

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया) : सभापति जी, यह सवाल बार बार लोक सभा में उठाया गया है, और मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय विभूति मिश्र जी ने इस सवाल को उठाकर एक बहुत अच्छा काम किया है। इस योजना का बिहार, उत्तर प्रदेश और नैपाल से भी सम्बन्ध है, यह ठीक है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह सब से सस्ती योजना है और इंडोगैन्जेटिक प्लेन से गुजरती है। इस बात को मंत्री जी ने कबूल किया था। लेकिन दुख है कि उसके बावजूद भी गंडक योजना पर सही ढंग से काम नहीं चल रहा है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात के लिये तैयार हैं कि नहीं, खुद मंत्री जी चलें और उस इलाके के जितने एम० पीज० हैं उनको मिला कर, इस बात की छान-बीन करें कि क्यों यह काम ढिलाई से चल रहा है? इस विषय में आप स्पष्ट जवाब दें कि आप ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं?

जिस समय संविद सरकार बिहार में थी उस समय एक योजना बनायी गयी थी और यह

[श्री कमल मिश्र मधुकर]

तय हुआ था कि प्रायरिटी के आधार पर काम कराया जाय। उस दौरान में काफी काम हुआ, जिस की आपने तारीफ भी की है। तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस ढंग से प्रायरिटी तय कर के उसके जरिये पूरा काम कम्प्लीट करके आगे बढ़ा जाय। जैसा माननीय विभूति मिश्र जी ने कहा है कि सारन जिले में जहां तहां जमीन खोद दी गयी है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। इस से लोगों को कठिनाई हो रही है। तो प्रायरिटी के आधार पर आप काम करने के लिये तैयार हैं कि नहीं ?

दूसरी बात यह है कि गंडक प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे असिस्टेंट और ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जो अपने रिश्तेदारों को ठेके पर काम देते हैं और उसके जरिये पैसा कमाते हैं। सरकार से अलग अपनी तनख्वाह लेते हैं। उसके कारण गड़बड़ियां होती हैं, उनकी रोक थाम होनी चाहिये। हमें इस बात की जानकारी है कि उनकी रोक थाम नहीं होती। सरकार बतलाये कि वह इस के लिये तैयार है या नहीं कि कोई निश्चित तिथि तय कर दी जाये, डेडलाइन बना दी जाये कि इस के अन्दर हम को गंडक योजना को पूरा कर लेना है। इससे आगे बढ़ने के लिये हम तैयार नहीं है। आप की योजना में जो खर्च पहले तय किया गया था उससे और भी बढ़ गया है और आगे भी बढ़ने जा रहा है। इस लिहाज से निश्चित तिथि तय कर लेनी चाहिये। उस तिथि के अंदर अंदर योजना को पूरा कर लेना चाहिये।

माननीय मन्त्री महोदय ने अपने पत्र में लिखा था कि गंडक योजना की फील्ड चैनल योजना के अंदर बनाई जायेगी, लेकिन जब मैंने चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर श्री एच० एच० ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि चैनल योजना के अन्दर नहीं बन सकती। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इसके न बनने से लोगों को बड़ी कठिनाई होगी। मन्त्री महोदय बतलायें कि जैसा उन्होंने पत्र में लिखा है उसके अनुसार इस काम को करवाने के लिये वह तैयार हैं या नहीं।

जहां तहां गंडक योजना के ड्रेनेज के ठीक न होने के कारण पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। किस ड्रेनेज के काम में ढिलाई पड़ रही है उसमें तेजी ला कर मंत्री महोदय कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं जिस से नहरों में पानी आ जाये और ड्रेनेज के द्वारा वह खेतों को मिले ताकि वह पानी बेकार न रहे। अगर यह पानी बेकार रहेगा तो सिंचाई नहीं हो पायेगी ?

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस में क्या ऐतराज है कि गंडक योजना को सेंट्रल योजना के रूप में चलाया जाये ? मेरा अन्दाज है कि बिहार सरकार भी इस से इन्कार नहीं करेगी। गंडक योजना बड़ी विशाल योजना है जिससे तीन राज्यों को लाभ होने वाला है। इससे हर साल बहुत काफी अनाज पैदा होगा और सारे देश को लाभ होगा।

SHRI RAMSEKHAR PRASAD SINGH (Chapra) : While supporting what has been said by the previous speakers, I want to ask two or three questions. It has been stated just now that in 1969 the estimate of this scheme was nearly Rs. 159 crores. What is the estimated cost of completing the scheme at this stage because two years have passed and circumstances have changed ? The estimate also must have changed.

Then, the Bihar Government had suggested at one stage that this scheme should be undertaken by the Central Government and the Central Government was also inclined to that. Now what is the objection in taking this up as a Central scheme and completing it ? My fear is that the State Government will not be able to complete it. So, I am asking this question.

Then, Shri Madhukar has said that though the canals have been constructed they are not working properly and we fear that after two or three years they will get filled and will have

to be dug again with consequent additional expenditure. What steps are the government taking to see that the canals do not get destroyed?

Lastly, though land has been acquired compensation has not beed paid. What steps are you going to take to give compensation quickly so that the people may not be put to difficulties? I want the Minister to give categorical replies to all these questions, including those questions asked by my hon. friends.

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): Madam Chairman, I wish to thank the hon. Members who participated in this discussion for the valuable suggestions made by them. I agree with all the observations which Shri Bibhuti Mishra made during his speech and also with the observations made by other hon. Members. As the hon. Member, Shri Mishra said, it had been our ambition to complete this project by 1970-71. Actually, our respected great leader, late President, Dr. Rajendra Prasad, used to ask me very often whether this project would be completed in his lifetime. I feel sorry we have been delaying his wishes in not completing this project so far. The main trouble was a very large increase in the estimate. The project was sanctioned in 1961. In 1961 the estimate was Rs. 52 crores. In 1969 the estimate went up to Rs. 159 crores and today I understand the cost will be Rs 206 crores. The Planning Commission has provided for the entire expenditure required to complete this project in the Fourth Plan but, unfortunately, there is a further excess of over Rs. 47 crores. So, another Rs. 47 crores are required in order to complete the project. That is the whole problem. This is not only in the case of Gandak but with other projects also. We have been considering for some time now how to check this excess in rise because nobody can plan even for the increasing cost on account of labour and materials. There is a big gap between the heavy increase that is taking place and the original estimate. I have been thinking for some time now whether the estimate prepared by various project authorities for the projects costing more than Rs. 30 crores should be checked by an independent agency. In the Central Water and Power Commission we cannot do this work. But these estimates should be scrutinised very carefully by an independent agency before they are put up for sanction. Out of Rs. 206 crores which will be the revised cost we have spent so far Rs. 116 crores, we have got still to spend another Rs. 90 crores. We have Rs. 50 crores in the Plan and another Rs. 40 crores have to be provided for in excess of what we have provided in the Plan if you want to complete this project by 1974 or probably it may be delayed by another one or two years. It may be we have got to accelerate the construction and try to finish by 1974, 1975 or 1976. This is so for as the estimates are concerned. The main problem, as the hon. Member said, is this. At one stage there had been pressure in the Parliament and outside that this project should be taken over by the Centre as it is a big project and also because this project comes in two States. Unfortunately, the policy in the Government as it is now decided is that the irrigation projects should be done by the State Government and the Central Government gives only finances. On account of that, the Project was not taken over. In May, 1968 I suggested I will take over at least Control Board so that we can have control like Chambal Control Board and re-constitute the Control Board. But, unfortunately, the then Governor of Bihar—the Governor of U. P. accepted—did not accept it and that is why it fell through. Now at this stage because it involves a major policy it is no use spending time over this issue whether it should be taken over by the Centre or not, but I agree with the hon. Member that when the Centre is giving so may crores of rupees it must have some control over these projects.

As Misraji said rightly, I was myself very anxious that in the case of a big project like this, where we are spending crores of rupees, the Chief Engineer should be at the site. It is not a matter of one rupee or a few lakhs of rupees. In the British days, in the case of a project costing Rs. 3 crores, the Chief Engineer was right on the spot. Here we are spending Rs. 206 crores and still the Chief Engineer is at Patna. I have often protested against that.

In fact, in the case of the Ghagra-Sarju project in U.P. a very big one, I have told the U.P. Government that the Chief Engineer should be located at site. In my recent visit to Lucknow I insisted that the Chief Engineer should be at the work-site. I am very glad that the U. P. Government has accepted it and is going to send the Chief Engineer there. No

[Dr. K. L. Rao]

doubt, there ase inconveniences for these big officers but the overall interest of the country has got to be looked to.

So far as Bihar is concerned, still there are Rs. 70 crores more to be spent on the Bihar side. We have spent Rs. 75 crores so for. An equal amount is still to spent. Therefore, it is of the utmost importance that the Bihar Chief Engineer in charge of this project must be at the site.

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : Why can you not take it over now ?

DR. K. L. RAO : I have submitted already that the policy of the Government of India is that irrigation being completely a state subject, it should be done by the State Government. I do not say whether I agree with it or not. Probably in the case of big works, where large amount of money is involved, it will be much better if the Centre does it. But at the moment it is not so.

What I am submitting is that there must be at least some measure of control. I agree with Shri Bibhuti Mishra that if we are not taking over the project, the next best thing to do is to have certain amount of control of the Centre. The Centre must not be simply refused like in the case of locating the Chief Engineer's head quarters. Now that hon. Members have expressed themselves, I have got more courage and I will ask the Bihar Government to place the Chief Engineer's headquarters at the site.

Also, we should try to find out what are the other measures that we should have. At least in projects, which are of a major nature, costing more than Rs. 30 crores, there must be some amount of control of the Centre ; otherwise, things will come to light rather late if there is any discrepancy.

In the Gandak Project, though we have spent Rs. 75 crores on Bihar side alone, the amount of irrigation that is being done is only 50,000 acres. It is very small quantity. Our aim is to irrigate as much as 30 lakh acres under the project. Out of 30 lakh acres to be irrigated in Bihar, we are doing only 50,000 acres. That means that there is something wrong. We have to look into that aspect.

I entirely agree with Mishraji that we must have an evaluation committee. As the project belongs to the State I am going to write to them the suggestion made by hon. Members and also add my own recommendation that we should have an evaluation committee to look into the whole affair and see how the money should be spent hereafter, so that as the canal proceeds more irrigation water may be supplied.

For example, the main canal has gone as far as 140 miles ; only 20 miles more are to be done. But the irrigation jone is only very little. Therefore it is necessary that we should concentrate from the beginning and try to finish mile by mile all the distributaries and water courses etc. There is going to be plenty of water in Gandak, much more than in the Sutlej river. The barrage has been completed. The water must be put to use as early as possible.

Therefore, a certain amount of looking into is required. I will request the State Government that they should setup a high evaluation committee to which I will also contribute some officers from the Centre.

Hon. Members have said that I should go. I plead guilty. I have not gone myself for the last one or two years. I will go as soon as the rains are over and would invite hon. Members also to come. At the moment you cannot go very far. In a project like this, there is a certain necessity to look into and programme so that the rupees we spent must result in the benefit for the nation. That is very neccsary.

18 hrs.

There is one thing more that I would like to submit to the hon. Members at this stage and that is that there is a persistent representation from various Engineers and also from the Bihar Government that farmers are obstructing that they do not give the land, that they want a bridge at every place, that they do not allow any water courses to be constructed and that they are not cooperating. I would say that there is an equal responsibility on the hon. Members to remove these difficulties. I think the hon. Members should arrange a conference in each district and try to do propaganda. I

would plead with the hon. Members belonging to various districts, Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga, etc., that they should organise some conference so that they can go to the people and do propaganda about irrigation. I must submit that in areas where there is no irrigation, it is very difficult for the people immediately to adopt new practices. The irrigation development requires certain demonstrations, certain convictions and vigorous propaganda. There is no doubt about it. That side has got to be looked after. Therefere, I would appeal to hon. Members to assist because we have come to a stage when assistance is required, when the people are required to be associated with this, so that they may feel that the project is theirs

Finally, there is one thing that I would like to submit....

PROF. S. L. SAKSENA : In the begining, the proposal was that Pharenda tahsil of the Gorakhpur district will also be irrigated by the Gandak project. But that has been left out.

DR. K. L. RAO : You mean further extension. That we will do. Out of 30 lakh acres, we are irrigating only 50,000 acres. There is plenty of water. There is no difficulty about the Gandak project.

Finally, there is one thing that I would like to submit. There is one difficulty that has arisen in Bihar. I must be frank about it. For example, in respect of the Kosi project, that is intended for irrigating 14 lakh acres and today we are irrigating only about 4 lakh acres. That is because the farmers do not take water. *Satta* system is there. When there is enough rain, they will not take water. Therefore, there is a certain amount of uncertainty. The same thing is happening to the Gandak project. I understand, this year, the canals are running full. But the people are not taking water because there is plenty of rainfall....

श्री बिभूति मिश्र : यह बात नहीं है । जब यह समर सीजन आया किसान पानी चाहते थे पानी नहीं मिला । जब पानी आज ज्यादा हो गया, बारिश हो गई तो आज पानी दे रहे हैं । हम लोग इरीगेशन माइंडेड पहले से हैं । त्रिवेणी कैनाल हमारे जिले में है । इरीगेशन माइंडेड हम हैं । लेकिन पानी समय पर आप नहीं देते, यह दिक्कत है ।

DR. K. L. RAO : I am giving the report that I have received from the Bihar Government that it is on account of the *Satta* system, on account of an option given to the farmers to take water or not. It is not so in many parts of India, say, for example in the south. There, a farmer has to pay whether he takes water or not, one the land has been asigned water. In Gandak the charges are about Rs. 16 per acre per crop. It is justified. Here, you are taking such a large project, such a costly project involving a huge amount of money. I would submit to the hon. Members to think over it carefully and calmly as to whether it is necessary that in respect of those lands which are going to be irrigated those persons should be asked to pay Rs. 16/- for *kharif* crop or some amount of money, for *kharif* crop so much, for *rabi* crop so much, and that will ensure the cooperation of the farmers also, the anxiety, to take water. Otherwise, at the moment, the farmer is not taking water. That is the actual experience in the case of the Kosi project. Most of the canals are ready. Out of 14 lakh acres, we are irrigating only about 4 lakh acres. (*Interruption*) There may be silting and want of water courses ; but this can be responsible only for a deficit of a few lakhs of acres, 2 lakhs or 3 lakhs. The point is, we have spent already several crores of rupees and something appreciable must result. The hon. Members should think over all these aspects. We want to take so many projects,—Bagmati, Western Kosi Canal and other projects—in North Bihar. Therefore, if we want to achieve success it must be seen that since we are spending heavily on the Project, we get some return out of that.

SHRI BIBHUTI MISHRA : What happened with regard to the Evaluation Committee ?

DR. K. L. RAO : I am writing to Bihar Government.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : It is past time and the discussion must conclude now.

DR. K. L. RAO : I am sorry I have taken more time.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet at 11 A. M. on Monday.

18.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 26, 1971/Sravana 4, 1893 (Saka).